

प्रकाशनार्थ

पटना, 27 जुलाई। बुधवार को पटना में एक ग्रीन डायलॉग को संबोधित करते हुए, अपर मुख्य सचिव (वित्त) डा. एस सिद्धार्थ ने कहा, “हम एक ऐसा हरित बजट लाने का लक्ष्य बना रहे हैं जो न केवल एक बजट के सकारात्मक पहलुओं का ध्यान रखे बल्कि इसके नकारात्मक पहलुओं का भी ध्यान रखे।” उन्होंने कहा कि राज्य के पास अंततः एक बहुत ही मजबूत हरित बजट होगा।

पर्यावरण और जलवायु अध्ययन केंद्र (सीएसईसी), आद्री के एक विशेष केंद्र और डेवलपमेंट अल्टरेटिव ग्रुप (डीएजी), दिल्ली द्वारा कार्यक्रम, ग्रीनिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर सस्टेनबल इकाॅनोमिक रिकवरी इन बिहार का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर श्री एस सिद्धार्थ मुख्य अतिथि थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपने लोगों को प्रशिक्षित करने और सिखाने की जरूरत है कि आपकी नीतियों को कैसे डिजाइन और री-डिजाइन किया जाए, जो बेहतर और शुद्ध हरित बजट के लिए हरित बजट के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का ध्यान रखता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता आद्री के सदस्य-सचिव प्रोफेसर प्रभात पी घोष ने की और संदर्भ डीएजी की गीतिका गोस्वामी ने रखा। इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ श्रीकांत कस्तूरी द्वारा ‘हरित उद्योगों और कृषि क्षेत्रों के लिए तकनीकी नवाचार’ पर एक व्याख्यान दिया गया, टेरी की विशेषज्ञ सहेली दास और शैली केडिया द्वारा दूसरा मुद्दा- बजट आधारित, वित्तपोषण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को हरित निवेश के लिए नवीन वित्तीय प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बाद में, एक गोलमेज सम्मेलन में ‘स्थायी सुधार और जलवायु लचीलापन के लिए बिहार के नीति परिदृश्य में रणनीतियों, प्राथमिकताओं और अंतराल’ पर चर्चा की गई। कृषि सचिव एन सर्वनन कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन जवाहर बाबू, बीआईए अध्यक्ष अरुण अग्रवाल और बीएसपीसीबी के सदस्य-सचिव एस चंद्रशेखर ने चर्चा में भाग लिया।

कृषि सचिव एन सरवनन कुमार ने कहा, “किसानों को अंततः जलवायु-अनुरूप कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और, राज्य ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज के विपणन के लिए उत्कृष्ट उपाय किए हैं।”

सीएसईसी, आद्री के उप निदेशक श्री विवेक तेजस्वी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)